areas of Thane, Kalyan and New Bombay and provision of municipal maintenance for about 2 lakh households, upgrading 315 hectares of slum areas and home improvement loans benefitting about 1 lakh households in the Bombay Municipal Corporation area. This is at an advanced stage, and I am happy to inform the hon. Member he can go and tell his constituency that this is coming.

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, बम्बई शहर में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी साल्ट लैंड्स हैं जिनपर अभी साल्ट नहीं बनाया जाता है। बम्बई म्युनिसिपल कार्पोरेशन के काम के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता थी लेकिन उसको वह भूमि अभी तक नहीं मिल सकी है। पहले एक बार मन्त्रीजी ने एक जवाब में बताया था कि अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की लैंड इम्मीडिएटली प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जायेगी उस पर स्लम इम्प्रूवमैंट स्कीम लागू की जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसी जिन जमीनों पर जहां झुग्गी-झोंपड़ी हैं, चाहे वह जमीन साल्ट अथारिटीज की हो, रेलवे की हो या सेन्ट्रल गवर्नमैंट के किसी काम की हो, जहां साल्ट लैंड अवेलेबल है, वहां उन लोगों को शिफ्ट करके स्लम इम्प्रूवमैंट योजना के तहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, स्वामी जी ने जो प्रश्न यहां उठाया था, वह केवल उन डिपार्टमैंट्स के बारे में है, जिनकी लैंड पर स्लम्स हैं। जिन लैंड पर नमक का काम चल रहा है, उसके लिए मुझे अलग से सूचना चाहिए। फिर भी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारी नीति है, उसके अन्तर्गत हम किसी को री-लोकेट नहीं करते, बल्कि जो जहां बैठा हुआ है, वहीं पर उसको सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं...

Provision of water supply including drinking water taps, sewer services, widening and paving of the existing lanes and roads, street lighting, community bath, latrines—these are the services for which Government of India provides assistance to the State Governments, with a view to improving the living conditions of the people in the slums. For this, there are criteria fixed, and based on those criteria, Government of India gives assistance to the various States; and Maharashtra Government has been given sufficient assistance in this regard.

Now about salt lands, if the hon. Member writes separately, I will be able to give the information.

SHRI JAGDISH TYTLER : My question relates not to Maharashtra, but to the slum areas in Delhi. Does the Minister have a policy for the slums which are on private lands ? I believe that in the 20-Point programme, there is a scheme for environmental improvement. The Minister should reply whether he will take these slum areas into consideration and spend money for environmental improvement, for the slums which have been existing for a very long time on private lands.

SHRI BUTA SINGH : It is a suggestion for action.

SHRI JAGDISH TYTLER : This is an improvement activity.

MR. SPEAKER : The Minister says it is a suggestion for improvement.

SHRI JAGDISH TYTLER : He has not completed his sentence, Sir.

SHRI BUTA SINGH : I have taken his suggestion for action.

SHRI SATISH AGARWAL : This is a suggestion for action, which will go to the Assurance Committee, and the Assurance Committee will examine it for years to come.

उत्तर प्रदेश में आपरेशन फ्लड-2

*685. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए की लागत पर आपरेशन फ्लड-2 योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने गांवों में दुग्ध समितियां बनाई गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) प्रत्येक समिति में कितने कर्मचारी काम पर रखे जाएंगे ; और

(ङ) ये समितियां दुग्ध उत्पादकों से किस भाव पर दूध खरीदेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां । आपरेशन फ्लड-2 परियोजना 111.06 करोड़ रुपए के अनुमानित परियोजना परिव्यय से उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है ।

(ख) दिसम्बर, 1984 तक 1978 समितियों के गठित किए जाने के लक्ष्य की तुलना में प्रादेशिक सहकारी डेरी संघ ने फरवरी, 1984 तक 1241 समितियां पहले ही गठित कर ली हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) दुग्ध उत्पादक समितियों के संचालक स्तर के आधार पर औसतन 2 या 3 व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं।

(ङ) इस समय उत्तर प्रदेश ग्रामीण डेरी सहकारी समितियों द्वारा दूध के लिए उत्पादकों को अदा की जाने वाली औसत कीमत 2.85 रुपये प्रति लिटर है। तथापि, उत्पादकों को दी जाने वाली कीमत समय-समय पर सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए संशोधित की जाती है।

श्री राम लाल राही : सर, यह आपरेशन फ्लड स्कीम सम्भवतः वर्ष 1970 से आरम्भ हुई है। जब से यह स्कीम आरम्भ हुई है, उससे पहले देश में बाहर से 3 हजार टन मिल्क पावडर आता था लेकिन बटर आयल बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन श्रीमन् सन् 1983-84 में सरकार ने लगभग 50 हजार टन मिल्क पावडर बाहर से मंगाया है और लगभग 10 हजार टन बटर आयल भी मगाया है। यह इनकी ऑपरेशन फ्लड स्कीम की कारगुजारी है, कारनामे हैं, श्रीमन्, देश में दूध की नदियां बहाने के नाम पर यहां इस योजना को लागू किया गया था, परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, औपरेशन फ्लड स्कीम के 1970 में चालू होने के बाद, जब पहली योजना बनी, तो उसमें निर्धारित लक्ष्य को ये पूरा नहीं कर पाये और इस कारण उसका समय बढ़ाना पड़ा। उस लक्ष्य को 1975 तक पूरा करना था, लेकिन उसकी अवधि को बढ़ाकर ये 1981 तक ले गए···

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल क्या बना···

श्री राम लाल राही : सर, मैं सवाल कर रहा हूं और बहुत माकूल सवाल है कि जब ये 1981 में भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये और वर्ष 1978 में दूसरी फ्लड स्कीम शुरू कर दी··· श्रीमन्, 1978 में दूसरी स्कीम शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन वहां पर उन्होंने पांच करोड़ रुपया दिया। गुजरात को केवल बम्बई को ही दूध सप्लाई करना है और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश, कलकत्ता और दिल्ली को दूध सप्लाई करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा फर्क आपने क्यों किया है ? उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों की उपेक्षा क्यों की गई है ? गुजरात को केवल बम्बई को ही दूध सप्लाई करना है, तो उसको ज्यादा धन क्यों दिया गया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष जी, यह सरासर असत्य है। इसमें कोई सत्य नहीं है। हर स्टेट को उसकी प्रोग्रेस के मुताबिक पैसा दिया जाता है। जितनी उसकी प्रोग्रेस है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है और परसपैक्टिव प्लान के अनुसार ही पैसा दिया जाता है। जहां तक यू०पी० की बात है जैसा मैंने अभी माननीय सदस्य को बताया यू०पी० के लिए टोटल आउटले 111.06 करोड़ रुपया किया गया है। यू०पी० में जो डेयरियां इस्टैबलिश हुई हैं, वे ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनकी प्रोक्योरमेंट और कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता है। एक बात यह भी है कि वहां कोआपरेटिव सोसायटीज इतनी डेवलप नहीं हुई हैं, प्राइवेट डेयरीज का वहां ज्यादा प्रभाव है। इसलिए इस मामले में पीछे है। मैं तो माननीय

सदस्य से अपील करता हूं कि वे खुद क्यों नहीं वहां को-आपरेटिव सोसायटीज आर्गेनाइज करते हैं। वहां को-आपरेटिव वर्कर्स न होने की वजह से इतनी को-आपरेटिव सोसायटीज डवेलप नहीं हुई हैं। इसलिए वह पीछे रहा है।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश में को-आपरेटिव सोसायटीज जो बनी हैं, वे ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए वे फेल हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां राज किसका है, यह काम किसको देखना चाहिए और को-आपरेटिव सोसायटीज कौन वहां पर बनाएगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बुनियादी सवाल है कि राज किसका है।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष जी, मैं यह बात फिर दोहराना चाहता हूं कि पहले जो फ्लड स्कीम उत्तर प्रदेश के लिए बनी थी, उसमें उसको 4 करोड़ रुपया दिया गया था और अब की बार एक ही करोड़ रुपया दिया गया है। पहले जब वह चार करोड़ रुपए में तरक्की नहीं कर पाई है, तो अब वह एक करोड़ रुपया से काम कैसे करेगी ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो को-आपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं, उनके निरीक्षण के लिए आपने कोई समिति बनाई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एल०के० झा की अध्यक्षता में फ्लड आपरेशन के सम्बन्ध में जो गड़बड़ हुई है, उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई है ? तो क्या आप पहले, दूसरे और तीसरे फ्लड स्कीम की जांच आप उससे करवायेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश को फ्लड स्कीम के माध्यम से 235.11 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। जहां तक को-आपरेटिव सोसायटीज ठीक न चलने की बात है, उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अपने हल्के में राही जी बना लें तो उनकी मदद करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम उनकी पूरी-पूरी मदद करेंगे। जहां तक झा कमेटी की बात है, वह कमेटी अपना काम कर रही है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी, तब मालूम हो जाएगा।

SHRI H.N. BAHUGUNA : He has not replied to the question why this import of powder milk and butter oil has increased.

MR. SPEAKER : The population has also increased.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : It is because the requirements of the people have increased. At the same time the production of milk also has increased. It is ture that the population also has increased.

MR. SPEAKER : Mr. Tewary.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना

*681. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अगली पंचवर्षीय योजना अवधि में एक बागवानी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना के लिए स्थान का चयन करते समय उन स्थानों पर भी विचार किया जायेगा जहां पर इस समय सघन बागवानी अनुसंधान केन्द्र हैं ; और

(ग) यदि हां, क्या इस प्रकार के विश्वविद्यालय/संस्थान की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में चौबटिया (अल्मोड़ा) पर भी विचार किया जाएगा ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) अगली पंचवर्षीय योजना में किसी बागवानी विश्व-